इकाई 4 पंचवर्षीय योजनाएं और ग्रामीण विकास

इकाई की रूपरेखा

4.1 लक्ष्य और उद्देश्य

4.2 परिचय

4.3 भारत में योजना का इतिहास और पंचवर्षीय योजनाओं की उत्पत्ति

4.4 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं

- 4.4.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)
- 4.4.2 दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)
- 4.4.3 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)
- 4.4.4 तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)
- 4.4.5 चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)
- 4.4.6 पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979)
- 4.4.7 रोलिंग प्लान (1978-80)
- 4.4.8 छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)
- 4.4.9 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)
- 4.4.10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)
- 4.4.11 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
- 4.4.12 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)
- 4.4.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)
- 4.4.14 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

4.5 नीति आयोग

- 4.5.1 उद्देश्य और विशेषताएं

4.6 सारांश

4.7 संदर्भ-सूची

4.8 अपनी प्रगति की जाँच करें – संभावित उत्तर

4.1 लक्ष्य और उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्न में सक्षम होंगेः

- ग्रामीण विकास में योजना प्रक्रिया की भूमिका को परिभाषित करना;
- नियोजन प्रक्रिया के इतिहास का अध्ययन करना;
- विभिन्न पंचवर्षीय योजना में क्रमिक परिवर्तनों की पहचान करना; और
- पांच साल की योजना से नीति आयोग में बदलाव को समझ पाएंगे।

4.2 परिचय

एक नए संविधान को अपनाने के बाद, भारत सरकार ने मार्च 1950 में देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की।

प्रथम प्रधानमंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष भी थे। वित्त मंत्री और योजना मंत्री आर्थिक विकास से जुड़ी विभिन्न मंत्रियों के साथ इसके अन्य सदस्य थे।

इन योजनाओं में उल्लिखित कुछ उद्देश्य राष्ट्रीय आय में बढोतरी, तेजी से औद्योगिकीकरण, पूर्ण रोजगार प्रदान करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। विकास की प्रक्रिया के साथ पहचाना गया केंद्रीय उद्देश्य जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोगों के लिए अधिक अवसर खोलना था।

भारत में योजना के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में संसाधनों के उचित प्रसारण की आवश्यकता थी। जबकि अल्पकालिक विकासात्मक उद्देश्य योजना से योजना में भिन्न होते हैं, नियोजन प्रक्रिया कुछ मायनों में कुछ दीर्घकालिक लक्ष्यों से प्रेरित थी। ये हैं:

क) **जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उच्च विकास दर प्राप्त करना:** अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण, औपनिवेशिक काल में देश ने एक मंद विकास देखा। लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे था। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य जीवन स्तर को ऊपर उठाना और राष्ट्रीय आय की बहुत अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना रहा है।

ख) **सामाजिक न्याय प्राप्त करना** : संविधान में निर्धारित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उपलब्धि को राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के रूप में घोषित किया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं राज्य की नीति का एक अंतर्निहित हिस्सा होने के नाते, सामाजिक न्याय उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में सामने आया।

इसके दायरे में आर्थिक और सामाजिक समानता और विकास में क्षेत्रीय संतुलन की उपलब्धि और आर्थिक शक्ति के एकाग्रता से बचना शामिल था। जनसंख्या के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष देखभाल सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों में से एक है।

ग) **आर्थिक आत्मनिर्भरता :** आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी पूरी नहीं होती है। इस संबंध में आत्मनिर्भरता क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के एक स्वाभाविक उद्देश्य के रूप में आई।

वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया गया। इसका सार इस तथ्य में निहित है कि अर्थव्यवस्था को घरेलू संसाधनों से काफी हद तक संतोषजनक दर पर अपनी निरंतर वृद्धि को वित्त पोषित करने में सक्षम होना चाहिए। विदेशी और बाहरी मदद न्यूनतम स्तर पर रखी जानी चाहिए। हालांकि, 1991 से इस संबंध में एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ जब केंद्र की सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और अर्थव्यवस्था को तेजी से आधुनिक बनाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सभी तरह से आगे बढ़े । विकास की रणनीति में सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक योजना शामिल थी; विकास के समाजवादी पैटर्न को बनाए रखने के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण; एक संतुलित विकास प्राप्त करना जो कृषि और उद्योग दोनों को विकसित करेगा; अधिकतम रोजगार प्रदान करना; पिछड़े क्षेत्रों के विकास को पूरा करना; पिछड़े वर्गों का उत्थान करना और समग्र सामाजिक कल्याण प्राप्त करना।

भारत में योजना बनाना एक खुली प्रक्रिया है। योजनाओं की तैयारी के साथ होने वाले अधिकांश विवाद और बहस सार्वजनिक हैं। प्रारंभिक कुल गणना और धारणाएं या तो स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं या आसानी से खत्म की जा सकती हैं, और योजनाओं के निर्माता न केवल संवेदनशील हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आलोचना और सुझावों के प्रति उत्तरदायी हैं। क्रमिक संशोधनों के माध्यम से मूल सूत्रीकरण से लेकर संसदीय प्रस्तुति तक, भारत में योजना निर्माण एक उत्तरदायी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ है और अंतिम दस्तावेज में इसकी परिणति एक खुले समाज के कामकाज की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। लेकिन अपनी प्रकृति से यह आर्थिक विकास के लिए एक इष्टतम रणनीति के मानचित्रण के दृष्टिकोण से कई समस्याएं भी उत्पन्न करता है ।

1947 के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था योजना की अवधारणा पर आधारित थी। यह योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015 के बाद से) द्वारा विकसित, निष्पादित और निगरानी की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, आयोग में एक नामित उपाध्यक्ष होता है, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना ने मार्च 2017 में अपना कार्यकाल पूरा किया। चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन एक पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गाडगिल सूत्र को अपनाया गया। राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन को निर्धारित करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। 2014 में चुनी गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की है, और इसके स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्त नाम) नामक एक थिंक टैंक का गठन किया है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

नोटः क) दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए संभावित उत्तर के साथ अपने उत्तर की जांच करें।

1) भारतीय संदर्भ में योजना बनाकर आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 भारत में योजना का इतिहास और पंचवर्षीय योजनाओं की उत्पत्ति

हालांकि भारत में नियोजित आर्थिक विकास 1951 में शुरू हुआ था, इस संबंध में सैद्धांतिक प्रयास पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बहुत पहले शुरू हो गए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, 1944 में बॉम्बे प्लान और गांधीवादी योजना, 1945 में पीपुल्स प्लान (भारतीय ट्रेड यूनियन की युद्ध के बाद पुनर्निर्माण समिति द्वारा), जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना इस दिशा में उठाए गए कदम थे।

पंचवर्षीय योजनाएं (एफवाईपी) केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1920 के दशक के अंत में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजनाएं (एफवाईपी) लागू की। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया है। चीन और भारत दोनों पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करना जारी रखते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपने ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया, विकास के लिए चीन की केंद्र सरकार ने अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुइहुआ) शब्द का प्रयोग किया।

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने 1951 में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया। यह प्रक्रिया मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई, जो देश के संसाधनों के कुशल दोहन, उत्पादन में वृद्धि और सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि एवं समुदाय की सेवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुसरण में थी। योजना आयोग पर देश के सभी संसाधनों का आकलन करने, कम संसाधनों को बढ़ाने, संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करने और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 1965 तक दो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई थीं, जब भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण ब्रेक लग गया था। लगातार दो वर्षों के सूखे, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और संसाधनों के क्षरण ने योजना प्रक्रिया को बाधित किया और 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाओं के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति और वर्ष 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया था। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद आठवीं योजना अंततः 1992 में शुरू की गई थी। पहली आठ योजनाओं के लिए बुनियादी और भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था, लेकिन 1997 में नौवीं योजना के शुभारंभ के बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हो गया है और देश में योजना पर वर्तमान सोच, सामान्य रूप से यह है कि इसे तेजी से एक सांकेतिक प्रकृति का होना चाहिए।

4.4 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं

4.4.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और सिंचाई, बिजली और परिवहन जैसे आर्थिक बुनियादी ढांचे को

मजबूत करने की दिशा में निर्देशित था। स्वाधीनता के समय देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी और खाद्य समस्या को हल करने के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई थी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करना, विपणन, मत्स्य पालन, पशुपालन, मृदा संरक्षण और वानिकी जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुधार के साथ-साथ अधिक खाद्य अभियान बढ़ाना उल्लेखनीय विशेषताएं थीं। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 54 मिलियन टन से बढ़कर 658 मिलियन टन हो गया और योजना के अंत में सभी कृषि जिन्सों का उत्पादन 22.2% बढ़कर 32% हो गया। इस योजना के दौरान कुल परिव्यय कृषि और सिंचाई पर खर्च किया जाना था। योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग हासिल कर लिए गए थे और यहां तक कि कुछ मामलों में भी पार हो गए थे। 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (सीडीपी) 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और बिजली, उद्योग और खनिज, ग्रामीण लघु उद्योग के विकास, परिवहन, रोजगार आदि पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, मेट्टर बांध, हीराकुंड बांध और भाखड़ा नांगल बांध को योजना (भारत सरकार, 1952) के दौरान सिंचाई कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। सरकार द्वारा कृषक श्रमिकों को आर्थिक निधि प्रदान की गई, कृषि में प्रशिक्षण, मृदा संरक्षण और अन्य संबंधित कृषि मुद्दों पर भी विचार किया गया। परिवहन और संचार, सामाजिक सेवाओं, रेलवे सेवाओं, टेलीग्राफ आदि में सुधार करने में भी महत्व दिया गया। इस योजना के दौरान, भारत में पांच स्थानों पर पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। उच्च शिक्षा यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की राष्ट्रीय आय की लक्षित वृद्धि 2.1% थी और 3.6% हासिल की।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

नोटः क) दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए संभावित उत्तर के साथ अपने उत्तर की जांच करें।

1) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दो उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

4.4.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

इस योजना में, कृषि से उद्योग पर जोर दिया गया था और कृषि विकास के लिए वास्तविक योजना व्यय का केवल 21% खर्च किया गया था। खाद्य उत्पादन 6.58 करोड़ टन से बढ़कर 7.97 करोड़ टन हो गया, जबकि निर्धारित लक्ष्य 8.05 करोड़ टन का था। गन्ने को छोड़कर सभी फसलों के उत्पादन में कमी थी। दूसरी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो भारतीय सांख्यिकीविद् पीसी महालनोबिस द्वारा 1953 में विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल है। खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्राम आवास परियोजना योजना ग्रामीण पुनर्निर्माण के प्रमुख कार्यक्रम थे। उर्वरकों, कीटनाशकों की आपूर्ति,

बीजों में सुधार आदि जैसे आवश्यक तत्वों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1962 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आईएडीपी) शुरू किया गया था। योजना के उद्देश्यों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, गरीबी में कमी, तेजी से औद्योगिकीकरण, धन में असमानता मंज कमी, रोजगार के अवसरों का बड़ा विस्तार आदि शामिल थे। (भारत सरकार, 1956)। जल विद्युत परियोजनाओं की तरह भारी उद्योग स्थापित किए गए और भारत में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में पांच इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। 1958 में होमी जे भाभा की अध्यक्षता में पहले अध्यक्ष के रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना एक शोध संस्थान के रूप में की गई थी। इस योजना में राष्ट्रीय आय की लक्षित वृद्धि 4.5% थी और 3.6% हासिल की गई थी।

4.4.3 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)

इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इस योजना में औद्योगिक विकास (20.1%) की तुलना में कृषि और सिंचाई को उच्च प्राथमिकता (20.5%) दी गई। योजना में समग्र कृषि उत्पादन को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उपलब्धियां निराशाजनक थीं। खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादन 1964-65 में 88.4 मिलियन टन और 1965-66 में 72.3 मिलियन टन था, जो 1965-66 की सूखे की स्थिति के कारण हुआ था। खाद्य उत्पादन में 30% के लक्ष्य के मुकाबले केवल 10% की वृद्धि हुई थी। नतीजतन, देश को घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बनाए गए थे। जमीनी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कई स्कूल शुरू किए गए हैं। इस अवधि के दौरान राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण एक राज्य जिम्मेदारी बन गई। राष्ट्रीय आय की लक्षित वृद्धि 5. 6% थी और 3.9% हासिल की गई। अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम, जनजातीय विकास खंड कार्यक्रम, ग्रामीण कार्य कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम आदि शुरू किया गया था। एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1962 में यूनिसेफ (अरोड़ा, 1986) के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्री-स्कूल बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक भोजन का उत्पादन और वितरण था। 1957 में बलवंत राय महता समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती राज, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने की सिफारिश की। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को पहली बार राजस्थान द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को अपनाया गया था।

4.4.4 तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)

1966-1969 तक विकास के लिए तीन अंतरिम वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इस अवधि के दौरान, लघु सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसके बाद कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम को अपनाया गया था। इस प्रकार, इस अवधि को भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान हरित क्रांति हुई और सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग और आपूर्ति में

उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए बफर-स्टॉक बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। खाद्यान्नों और उनकी कीमतों की संख्या। एचवाईवी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण, 1968-69 में 95.6 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गया था।

4.4.5 चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)

चौथी योजना में कृषि क्षेत्र के लिए दो उद्देश्य थे :

i) वर्ष 1969-78 के दशक में खाद्य उत्पादन में लगभग 5% प्रति वर्ष की निरंतर वृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करना; और

ii) छोटे किसानों, शुष्क क्षेत्रों के किसानों और कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से को कृषि विकास की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके लाभ को साझा करने में सक्षम बनाना।

वार्षिक योजनाओं के दौरान शुरू की गई हरित क्रांति का अच्छा परिणाम हुआ और विशेष रूप से गेहूं उत्पादक बेल्ट में किसान उच्च फसल उत्पादन (एचवाईवी) खेती को अपनाने के इच्छुक थे। खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादन 129 मिलियन टन की लक्षित वृद्धि की तुलना में 1973-74 में 1047 मिलियन टन था। इस योजना में 'सामाजिक न्याय' और 'गरीबी हटाओ' पर जोर दिया गया था। इसमें गरीब और दलित वर्गों के सुधार पर जोर दिया गया। सरकार ने मान्यता प्राप्त 14 प्रमुख भारतीय बैंकों बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय बैंक के रूप में परिवर्तन पर जोर दिया। राष्ट्रीय आय की लक्षित वृद्धि 5.7% थी और वास्तविक वृद्धि 3.3% हासिल की गयी। इस अवधि के दौरान ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश स्कीम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, जनजातीय क्षेत्र विकास एजेंसी और पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गए थे। पारिस्थितिक संतुलन की बहाली, मिट्टी और नमी संरक्षण, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि का विकास, सिंचाई संसाधनों का प्रबंधन आदि इस योजना (भारत सरकार, 1969) के उद्देश्य थे। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पीआईआरईपी), को पायलट आधार पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में शुरू और कार्यान्वित किया गया था। । लघु और सीमांत किसान विकास एजेंसी (एसएफडीए) और सीमांत किसान और कृषि मजदूर विकास एजेंसी (एमएफएएलडीए) को खोदे गए कुएं, पंप सेट, ट्यूबवेल प्रदान करके और पशुपालन के लिए भेड़ और बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि ऋण उपलब्ध करा के छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था।। 1970-1971 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी) चार राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों को क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, सिंचाई विकास, सड़क निर्माण, भूमि सुधार आदि द्वारा देश के आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाना था। 1974 में, गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए चार योजनाओं के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) शुरू किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों के लिए न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन, निवारक चिकित्सा, पोषण, शहरी मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में सुधार, ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण आदि प्रदान करना था।

4.4.6 पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979)

पांचवीं योजना के दौरान, कृषि विकास और सिंचाई के लिए 8080 करोड़ रुपये (योजना परिव्यय का लगभग 21%) खर्च किए गए थे। इस योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत उत्पादन बीज (एचवाईवी) खेती के प्रसार, उर्वरक, कीटनाशकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग को प्राथमिकता दी गई थी। योजना में (i) छोटे और सीमांत किसान (ii) शुष्क कृषि तकनीक, (iii) धान जैसी अन्य फसलों के लिए उन्नत उत्पादन बीज (एचवाईवी बीज) विकसित करना, (iv) खारी और क्षारीय मिट्टी पर सामाजिक संरक्षण उपाय और रेगिस्तानी भूमि सुधार पर विशेष जोर भी दिया गया था। इस योजना के दौरान, खाद्यान्न के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई (232.5 मिलियन टन)। लेकिन दालों और तिलहन, धान का उत्पादन स्थिर रहा और आम आदमी के लिए काफी कठिनाई का कारण बना। इस योजना को 1979 के बजाय 1978 में समाप्त कर दिया गया था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए युवाओं का प्रशिक्षण शुरू किया गया। 1975-1976 में भारत सरकार ने ग्रामीण भीड़ के कमजोर वर्गों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम (एसएलपीपी) शुरू किया। मरुभूमि क्षेत्रों के लोगों के उत्पादन, आय, रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए 1977-1978 में मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम पांच राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) के 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में शुरू हुआ। 15 अगस्त, 1979 को सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRYSEM) शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को एक उत्पादक शक्ति में बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवाओं के 18-35 आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण के लिए पात्र थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पुरुष और महिला दोनों सामान्य श्रेणियों के साथ पात्र थे। प्रशिक्षण औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक, कृषि विघन केंद्रों, नेहरू युवा केंद्रों, खादी और ग्रामोद्योग केंद्रों, स्वैच्छिक के माध्यम से प्रदान किया जाता था। संगठन और प्रतिष्ठित मास्टर कारीगरों के माध्यम से भी (भारत सरकार, 1974)। राष्ट्रीय आय की लक्षित वृद्धि 4.4% थी और वास्तविक वृद्धि 4.9% थी।

4.4.7 रोलिंग प्लान (1978-80)

दो छठी योजनाएं थीं। सरकार ने 1978-1983 के लिए एक योजना प्रस्तुत की। हालांकि, सरकार केवल 2 साल तक चली। कांग्रेस सरकार 1980 में सत्ता में लौटी और एक अलग योजना शुरू की।

4.4.8 छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

छठी पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कृषि और ग्रामीण विकास में तीव्र वृद्धि पर काफी निर्भर करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर पैदा करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण की ताकतों को मजबूत करना था। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के लिए भूमि सुधार और संस्थान निर्माण के कार्यान्वयन की गति को तेज करना था। इस योजना का उद्देश्य

कृषि उत्पादन में 3.8% वार्षिक वृद्धि करना था। लेकिन, वास्तविक विकास दर 4.3% थी। इस योजना को आधिकारिक तौर पर विशेष रूप से कृषि निधि पर इसकी सफलता, जन्म नियंत्रण के लिए अनुकूलित एक-बच्चे की नीति, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) आदि के कारण एक बड़ी सफलता के रूप में आयोजित किया गया था। 1980 में, काम के बदले में भोजन की नीति ने जगह ली और NREP शुरू किया। रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सृजन, ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार आदि NREP के प्रमुख उद्देश्य थे। एसएफडीए, एमएफएएलडीए, एनआरईपी, आईआरडीपी, डीपीएपी और एमएनपी जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। वे 1982 के 20सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा थे। 1982 में, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (DWCRA) तैयार किया गया था। DWCRA का लक्ष्य समूह IRDP के रूप में है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) 1983 में प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों के लिए मजदूरी आंशिक रूप से भोजन में और आंशिक रूप से नकद में दी जाती है। आरएलईजीपी का जेआरवाई कार्यक्रम के साथ विलय हो गया। राष्ट्रीय आय की लक्षित वृद्धि 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि 5.3% थी।

4.4.9 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

सातवीं योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में 4% की वार्षिक औसत वृद्धि करना था। योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 39,770 करोड़ रुपये आवंटित किए गए (कुल योजना परिव्यय का 22%)। योजना के दौरान अपनाए गए प्रमुख कार्यक्रमों में पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल-शेड कार्यक्रम, राष्ट्रीय तेल-बीज विकास परियोजना और सामाजिक वानिकी शामिल थे। दुर्भाग्य से, इस योजना के पहले तीन साल खराब मानसून वर्ष थे। नतीजतन, इन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन को एक सेट-बैक मिला। हालांकि, पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके लिए कृषि उत्पादन में 4.1% की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना का गठन कई गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के साथ किया गया था। 1 अप्रैल, 1989 को जवाहर रोजगार योना को पहले की दो रोजगार योजनाओं नामत आरएलईजीपी और एनआरईपी के विलय के साथ शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए रोजगार, ग्रामीण आर्थिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना जेआरवाई के उद्देश्य थे। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 80:20 के अनुपात में व्यय साझा करती थी। द मिलियन वेल्स स्कीम (एमएसडब्ल्यू) कार्यक्रम 1988-1999 में शुरू किया गया था जिसमें ग्रामीण गरीबों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छोटे और सीमांत किसानों और भू-भाग की योजना और भूमि सीमा सहित मुक्त बंधुआ मजदूरों को निशुल्क खुले नकली कुएं प्रदान किए गए थे। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) आरएलईजीपी का एक एकीकृत हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और बंधुआ मजदूरों से संबंधित ग्रामीण जनता में से सबसे गरीब लोगों को आवासयी घर प्रदान करना था। घरों में धुआं रहित रसोईघर और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास आय का लक्ष्य 5.05% था और इसकी वास्तविक वृद्धि 5.8% थी।

4.4.10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

इस योजना का मूल उद्देश्य पिछले 40 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादकता और उत्पादन में पहले से ही हासिल किए गए लाभों को समेकित करना; बढ़ती आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बनाए रखना; किसानों की आय में वृद्धि करना; कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना; और कृषि निर्यात को बढ़ाना था। इसके लिए कुल योजना परिव्यय का 22% (93,680 करोड़) कृषि और सिंचाई के लिए रुपये आवंटित किए गए थे। इस योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 41% प्रति वर्ष की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, विभिन्न योजना अवधियों के दौरान, सरकार ने कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण महत्व दिया था और विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया था। 1989-1991 की अवधि में भारत में एक आर्थिक अस्थिरता थी और इसलिए कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 और 1992 के बीच, केवल वार्षिक योजनाएं थीं। निजीकरण और उदारीकरण पंचवर्षीय योजना की इसी अवधि से शुरू किया गया था। उद्योगों का आधुनिकीकरण आठवीं योजना का लक्ष्य था। इस योजना के दौरान भारत 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य थे – तेजी से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, पर्यटन प्रबंधन विकसित करना, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज की भागीदारी ग्रामीण विकास, नगर पालिका कानून, गैर-सरकारी संगठन और सत्ता का विकेंद्रीकरण और सरकारी नीतियों में लोगों की भागीदारी। इस योजना में, लक्ष्य राष्ट्रीय विकास आय 5.6% थी और वास्तविक राष्ट्रीय विकास आय 6.78% हासिल की। इस योजना अवधि के दौरान प्रमुख कार्यक्रम आईआरडीपी, जेआरवाई, आईएवाई और एमडब्ल्यूएस थे।

4.4.11 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

नौवीं पंचवर्षीय योजना को चार महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित किया गया थाः (i) जीवन की गुणवत्ता, (ii) उत्पादक रोजगार का सृजन, (iii) क्षेत्रीय संतुलन और (iv) आत्मनिर्भरता। लक्ष्य वृद्धि 6.5% थी लेकिन वास्तविक वृद्धि 5.35% हासिल की गई। यह 1997-2002 से कठोर औद्योगीकरण, मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, रोजगार में वृद्धि, सभी के लिए शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, प्रदान करने जैसे जीवन के बुनियादी ढांचे को प्रदान करने जैसे प्रमुख उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि। 1999-2000 के दौरान आईआरडीपी, ट्राइसेम, डीडब्ल्यूसीआरए, एसआईटीआरए, एमडब्ल्यूएस को एकीकृत कर 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना (एसजेजीएसवाई) के रूप में नया स्व-रोजगार कार्यक्रम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, पोषण संबंधी भोजन की सुरक्षा, जल आपूर्ति, महिलाओं और सामाजिक रूप से नुकसान वाले समूहों का सशक्तिकरण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय आदि प्रदान करना था। (भारत सरकार, 1997)।

दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय संकट (1996-97) भारतीय अर्थव्यवस्था में भी समग्र मंदी का कारण बना। जबकि उदारीकरण प्रक्रिया की अभी भी आलोचना हो रही थी, भारत 1990 के दशक की शुरुआत में राजकोषीय गड़बड़ी से बाहर था। इस योजना ने 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर को लक्षित किया और समयबद्ध सामाजिक उद्देश्यों की ओर भी निर्देशित किया।

इसके अलावा, योजना में समयबद्ध तरीके से पूर्ण जनसंख्या कवरेज प्राप्त करने की दृष्टि से सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें शामिल हैं:

- पीने का सुरक्षित पानी
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
- आश्रय-रहित परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता
- बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता
- सभी गांवों और बस्तियों की कनेक्टिविटी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना ।

4.4.12 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजेजीएसवाई) के अंतर्गत 125 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने पर जोर दिया गया जिससे सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने वाली 25 लाख महिलाओं को लाभ होगा, कौशल और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए प्रशिक्षण, लगभग 5 लाख ग्रामीण महिलाओं के लिए ऋण संपर्क व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जेजीएसवाई और ईए का विलय कर दिया गया और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) नामक एक नई स्कीम 15 अगस्त, 2001 से शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क के लिए वर्ष 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की गई थी। इस योजना के दौरान उच्च गरीबी, बेरोजगारी आदि की वास्तविक समस्याओं की जांच करने के लिए एक नई योजना अर्थात राष्ट्रीय सम विकास योजना शुरू की गई थी जो विकास के लिए बाधाओं को दूर करेगी और विकास प्रक्रिया में तेजी लाएगी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 75: 25 के अनुपात में स्थापित की गई है। लक्ष्य वृद्धि राष्ट्रीय आय का 8.1% थी और वास्तविक वृद्धि 7.7% हासिल की।

इस योजना के कुछ प्रमुख पहलू थे:

- 10 साल में दोगुनी हुई प्रति व्यक्ति आय
- उच्च विकास दर को लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता में बदलना चाहिए
- निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित करना
- विकास के कारक के रूप में शासन पर विचार
- सभी क्षेत्रों में नीति और संस्थागत सुधार
- कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्राथमिक गतिशील शक्ति (पीएमएफ) के रूप में घोषित करना
- सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) पर जोर।

4.4.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का गठन दो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात भारत निर्माण कार्यक्रम और प्रमुख कार्यक्रम के साथ किया गया था ताकि जीवन की स्थिति के साथ-साथ आजीविका में सुधार के अवसर प्रदान किए जा सकें। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के तहत समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके, सिंचाई की औसत दर का निर्माण, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क, भारत में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विद्युतीकरण, शुद्ध रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण की तात्कालिकता की भावना प्रदान करना है। पेयजल आदि जो भारत निर्माण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ग्रामीण बसावटों के लिए सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई थी । प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन (एमडीएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) स्वच्छता अभियान (टीएससी), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) शामिल थे। बीआरजीएफ ने पंचायती राज संस्थाओं (भारत सरकार, 2007) की भागीदारी के माध्यम से अधिक सहभागी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) को प्रतिस्थापित किया है।

11वीं योजना का शीर्षक 'तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर' था। इसमें लगभग 9 प्रतिशत की उच्च विकास दर की परिकल्पना की गई थी, जिसका अर्थ है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर। इसने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार भी सुनिश्चित किया। 11वीं योजना के दृष्टिकोण में शामिल हैं:

- गरीबी कम करने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ तेजी से विकास
- गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच
- शिक्षा और कौशल के विकास के माध्यम से सशक्तिकरण
- सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उपयोग करना
- पर्यावरणीय स्थिरता
- लैंगिक असमानता को कम करना
- समग्र शासन में सुधार।

4.4.14 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित थी और देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। निम्नलिखित सात प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे थे। मनरेगा, एनएफआरएलएम, आईएवाई, एनआरडीडब्ल्यूपी, टीएसपी, आईडब्ल्यूडीपी, पीएमजीएसवाई, आरजीजीवीवाई (भारत सरकार, 2012)।

इनके अलावा, भारत सरकार ने गरीब वर्गों के उत्थान के लिए अन्य कार्यक्रम जैसे ग्राम आत्मनिर्भरता योजना, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के सदस्य, महिलाओं के लिए एकीकृत स्वच्छता परिसर, स्वच्छ ग्राम अभियान और ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अवसंरचना विकास का पूंजी कार्यक्रम, ग्राम

प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय भवनों का निर्माण, जल निकायों का कायाकल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन आदि शुरू किए। इस योजना के अनुसार, 'इसे भारत के इस तरह से आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से निर्देशित किया जाना चाहिए जो एक विकास प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों के जीवन स्तर में व्यापक आधार पर सुधार सुनिश्चित करेगा जो अतीत की तुलना में तेज, अधिक समावेशी और पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ भी है। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 9 प्रतिशत की वृद्धि दर
- कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और योजना अवधि के दौरान 4 प्रतिशत की औसत वृद्धि करना
- मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना
- सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए, यह सुनिश्चित करना कि वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति प्रति वर्ष 6.5-7 प्रतिशत की दर से बढ़े।
- एक समग्र जल प्रबंधन नीति विकसित करना
- भूमि अधिग्रहण के लिए नए कानून का सुझाव देना
- स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में बड़ा निवेश
- राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया पर जोर
- उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग।

4.5 नीति आयोग

भारत में योजना गतिविधियों की भूमिका योजना आयोग (2014 तक) द्वारा निभाई गई थी, बाद में नीति आयोग, एक थिंक टैंक ने योजना दृष्टिकोण को और अधिक बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग को समावेशी और नीचे-ऊपर वाले दृष्टिकोण से बदल दिया । नीति आयोग के चार्टर में इसे एक ऐसे निकाय के रूप में वर्णित किया गया है जिसे भारत की संघीय और जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए।

29 मई 2014 को, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना आयोग को "नियंत्रण आयोग" के साथ बदलने की सिफारिश के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। 13 अगस्त 2014 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को खत्म कर दिया। 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की। नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने की थी।

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है	यह अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
यह व्यापक विशेषज्ञता से सदस्याता प्राप्त करता है।	इसकी विशेषज्ञता सीमित थी।

यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं।	राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शक के रूप में भाग लिया।
सचिवों को प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त सीइओ के रूप में जाना जाएगा।	सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से की गई।
यह नियोजन के निचले स्तर से ऊपर के दृष्टिकोण पर ध्यान केंदित करता है।	इसने ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोंण अपनाया।
इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियां लागू की और धन के आवंटन को स्वीकृत परियोजनाओं के साथ जोड़ दिया।
इसके पास धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं, जो वित्त मंत्री में निहित हैं।	इसके पास मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ थी।

NITI आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जिसे राज्य की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की सरकारें निचले स्तर के दृष्टिकोण का उपयोग करती हैं। इसकी पहलों में "15 साल का रोड मैप", "7 साल का विजन, रणनीति और कार्य योजना", अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार (मॉडल लैंड लीजिंग कानून, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के सुधार) शामिल हैं। इसमें विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों का उप-समूह, स्वच्छ भारत पर मुख्यमंत्रियों का उप-समूह अभियान, कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों का उप-समूह, कृषि और गरीबी उन्मूलन पर टास्क फोर्स, और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया व्याख्यान श्रृंखला आदि शामिल है।

4.5.1 नीति आयोग के उद्देश्य और विशेषताएं

उद्देश्य

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- नियमित आधार पर राज्यों के साथ संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर उन्हें उत्तरोत्तर समेकित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हो सकते हैं।
- रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलों को डिजाइन करना, और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना। निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखे गए सबक का उपयोग अभिनव सुधार करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आवश्यक मध्य-पाठ्यक्रम सुधार शामिल हैं।
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंक, साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सामूहिक समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली बनाना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को बनाए रखने के लिए, सतत और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार होने के साथ-साथ उनके प्रसार में मदद करना हितधारक।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत किया जा सके।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडा और ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के निष्पादन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियों को करना।

सुविधाएं

नीति आयोग आवश्यक संसाधनों, ज्ञान और कौशल के साथ खुद को एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए रणनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम करेगा।

नीति आयोग की गतिविधियों के सभी पहलुओं को चार मुख्य प्रमुखों में विभाजित किया जा सकता है:

1) डिजाइन नीति और कार्यक्रम रूपरेखा
2) सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
3) निगरानी और मूल्यांकन
4) थिंक टैंक और ज्ञान और नवाचार हब।

2017 के बाद, भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में, 'नीति आयोग' ने कार्यात्मक रूप से खुद को विभिन्न समूहों में विभाजित किया, जो राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय मुद्दों और प्राथमिकताओं की जांच और देखने के लिए जिम्मेदार हैं। नीति आयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के भीतर ग्रामीण विकास विभाग को उनके द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं में समग्र नीति मार्गदर्शन प्रदान करके ग्रामीण विकास का मार्गदर्शन करता है। यह विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी भी करता है।

अपनी प्रगति की जांच करें 3

नोट: क) दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए संभावित उत्तर के साथ अपने उत्तर की जांच करें।

1) योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर का हवाला दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

4.6 सारांश

कृषि ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सीमित उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को किसानों के करीब लाने के लिए अगली योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि आदानों की आपूर्ति, कृषि मशीनरी, सिंचाई सुविधाओं, फसल पैटर्न, कृषि प्रसंस्करण और स्वास्थ्य, आवास सुविधाओं, स्वच्छता, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे सामान्य पहलुओं जैसे

अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कृषि और ग्रामीण विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों मुख्य रूप से योजना बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और निगरानी और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए भारत के योजना आयोग द्वारा डिजाइन की गई योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के साथ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण और सामाजिक-आर्थिक और राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए नीति निर्माण में लोकप्रिय भागीदारी आवश्यक है। ग्रामीण विकास समयबद्ध उन्मुख, सहभागी उन्मुख, विकेन्द्रीकृत उन्मुख, सामूहिक उन्मुख, सुधार उन्मुख, इक्विटी उन्मुख, संस्थागत उन्मुख होगा।

4.7 संदर्भ

अरोड़ा आरसी (1986). एकीकृत ग्रामीण विकास, एस चंद एंड कॉम , नई दिल्ली, पृ.34 ।

सीएसओ एमओएसपीआई (2014). केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

जोआचिम योन ब्रौन, अशोक गुलाटी, पीटर हेज़ेल, मार्क डब्ल्यू रोजग्रांट और मैरी रूएल (2005). भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास – रणनीतिक मुद्दे और सुधार विकल्प, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई), वाशिंगटन, डीसी, पृ. 1-6।

एमओए जीओआई (2014). वार्षिक रिपोर्ट – 2014-15, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली, पृ. 1।

एमओआरडी (2005). ग्रामीण विकास मंत्रालय 2005, पृ. 1

एमओआरडी (2012). ग्रामीण विकास मंत्रालय 2012, पृ.

प्रभा, ब्रेजेश कुमार, एसके गोयल, आरके गोयल और श्री राम सिंह (2015). पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारतीय कृषि और ग्रामीण विकासः एक मूल्यांकन। एग्रीवेज जर्नल. 3 (1): 41-47.

सरकार बी (2014). भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमः पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में एक अध्ययन. ग्लोबल जर्नल फॉर सिसर्च एनालाइसिस, 3 (1): 45-47।

4.8 अपनी प्रगति की जाँच करें – संभावित उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें 1

1) भारत में योजना का अंतिम उद्देश्य बड़े पैमाने पर समाज के जीवन स्तर में व्यापक आधार पर सुधार प्राप्त करना है। आय और रोजगार के विस्तार के लिए तीव्र विकास आवश्यक है। यह सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। भारत में योजना के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में संसाधनों के उचित प्रसारण की आवश्यकता थी। जबकि अल्पकालिक विकासात्मक उद्देश्य योजना से

योजना में भिन्न होते हैं, नियोजन प्रक्रिया कुछ मायनों में कुछ दीर्घकालिक लक्ष्यों से प्रेरित थी।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

पहली पंचवर्षीय योजना का दो स्तरीय उद्देश्य थाः

क) द्वितीय विश्व युद्ध और देश के विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन को ठीक करना।

ख) साथ ही सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया शुरू करना जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना। इस योजना में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना का उद्देश्य निवेश की दर को राष्ट्रीय आय के 5% से 7% तक बढ़ाना भी था। इस योजना में हासिल की गई विकास दर 3.6% थी।

अपनी प्रगति की जाँच करें 3

1) **नीति आयोग और योजना आयोग**

नीति आयोग को राज्यों पर नीतियां थोपने का अधिदेश या शक्तियां नहीं दी गई हैं। नीति आयोग मूल रूप से एक थिंक-टैंक या एक सलाहकार निकाय है। योजना आयोग के पास राज्यों और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नीतियां थोपने की शक्ति थी।

निधियों के आवंटन की शक्तियां नीति आयोग को नहीं दी गई हैं। शक्तियां वित्त मंत्रालय के पास हैं। योजना आयोग के पास राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।

नीति आयोग में राज्य सरकारों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठकों में भाग लेने के अलावा राज्य सरकारों की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। राज्य सरकार की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तक सीमित थी।

आवश्यकताओं के आधार पर, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में उपराज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री थे। योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास आयोग को रिपोर्ट करना था।

नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। योजना आयोग के सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी।

नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या योजना आयोग की संख्या से कम हो सकती है पिछले योजना आयोग में आठ पूर्णकालिक सदस्य थे।

नीति आयोग	योजना आयोग
नीति आयोग को राज्यों पर नीतियां थोपने का अधिदेश या शक्तियां नहीं दी गई हैं। नीति आयोग मूल रूप से एक थिंकटैंक या एक सलाहकार निकाय हैं।	योजना आयोग के पास राज्यों और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नीतियां थोपने की शक्ति थी।
निधियों के आवंटन की शक्तियां नीति आयोग को नहीं दी गई हैं। शक्तियां वित्त मंत्रालय के पास हैं।	योजना आयोग के पास राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।
नीति आयोग में राज्य सरकारों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।	बैठकों में भाग लेने के अलावा राज्य सरकारों की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। राज्य सरकार की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तक सीमित थी।
आवश्यकताओं के आधार पर, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।	योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
नीति आयोग की गवर्निंग कांसिल में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं।	राष्ट्रीय विकास परिषद में उपराज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री थे। योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास आयोग को रिपोर्ट करना था
नीति आयोग के आयोग के सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है।	योजना आयोग के सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी।
नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या योजना आयोग की संख्या से कम हो सकती है	पिछले योजना आयोग में आठ पूर्णकालिक सदस्य थे।

अन्य संदर्भ-ग्रंथ

दाश, बी.एम. और सिंह, ए.पी. (2011). पंचवर्षीय योजना की तुलना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आयामों में परिवर्तन; ग्रामीण विकास में आधुनिक दृष्टिकोण (संपादन, चटर्जी, एस.), नई दिल्ली प्रकाशक, पृष्ठ 71-78।